

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298]
No. 298]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 1990/असाढ़ 27, 1912
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 1990/ASADHA 27, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन की रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1990

सा. का. नि. 647 (अ):—राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्न-
लिखित उद्घोषणा सर्वसाधारण के सूचनायें प्रकाशित की जा रही हैं:—

यतः मुझे, भारत के राष्ट्रपति, आर. वेंकटरामन को अम्बू व कश्मीर
राज्य के राज्यपाल ने एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, और इस रिपोर्ट तथा
मुझे प्राप्त अन्य सूचना पर विचार करने के बाद मेरा समाधान हो गया है
कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें उस राज्य का नामन भारत
के संविधान, जैसा कि वह उस राज्य पर लागू है, (जिसे इसमें इसके
पश्चात् "संविधान" कहा गया है) और अम्बू व कश्मीर के संविधान (जिसे
इसमें इसके पश्चात् "राज्य संविधान" कहा गया है) के उपबंधों के अनुसार
अर्थात् बताया जा सकता है;

अतः अब मैं, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा
उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते
हुए एतद्वारा उद्घोषणा करता हूँ कि मैं—

(क) संविधान और राज्य संविधान के अधीन उक्त राज्य की सरकार
के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित शक्त

उनके द्वारा प्रयोज्य सभी शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति
के रूप में स्वयं संभालता हूँ,

(ख) उद्घोषित करता हूँ कि उक्त राज्य के विधान मंडल की
शक्तियों संभल द्वारा प्रत्येक उक्त प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य
होंगी; और

(ग) निम्नलिखित आनुवंशिक और पारिजातिक उल्लंघन करता हूँ जो
इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावित बनाने के लिए मुझे
आवश्यक या वांछनीय पतीत होते हैं; अर्थात्:—

(1) पूर्वोक्त के अनुसार, इस उद्घोषणा के खण्ड (क) के
आधार पर मेरे द्वारा संभाले गए कृत्यों तथा शक्तियों
का प्रयोग करने में मेरे लिए, भारत के राष्ट्रपति के
रूप में, उन सीमा तक जिस तक मैं लोक सभों, उक्त
राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्वक
होगा;

(2) संविधान के तथा राज्य संविधान के निम्नलिखित उपबंधों
के प्रवर्तन को एतद्वारा निरस्तित किया जाता है,
अर्थात्:—

संविधान के अनुच्छेद 3 के पञ्च परमार्थ का उक्त
भाग जितने का संबंध राष्ट्रीय द्वारा राज्य विधानमंडल

के प्रति निर्देश है, और उस अनुच्छेद का दूसरा परन्तुक ;

संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (2) का उत्तरा भाग जितने का संबंध भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों को राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है ;

राज्य संविधान की धाराएं 35 से 41 तक (जिसमें वे दोनों सम्मिलित हैं), धारा 43 का उत्तरा भाग जितने का संबंध राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच कार्य के बंटवारे से है, धारा 44, धारा 53 की उपधारा (1) और उपधारा (2) का खंड (क), धाराएं 54, 55, 56 तथा 57, धारा 58 के खंड (ख) और (ग) और उसका पहला परन्तुक, धारा 59, धारा 60, धारा 61 की उपधारा (2), जहाँ तक उनका संबंध धारा 58 के खंड (ग) और पहले परन्तुक से तथा धारा 60 से है ;

धाराएं 65, 66, 67, 71 और 72, धाराएं 74, 75 और 76, धारा 77 की उपधारा (3) तथा (4), धाराएं 85 से 88 तक (जिसमें वे दोनों सम्मिलित हैं) और धारा 137 का उत्तरा भाग जितने का संबंध जहाँ तक स्थित रिपोर्ट के राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है ;

- (3) संविधान में, और राज्य के संविधान में, राज्यपाल के प्रति किसी निर्देश का अर्थ उक्त राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के प्रति निर्देश लगाया जाएगा, और संविधान में तथा राज्य के संविधान में राज्य के विधान मंडल या उसके सदस्यों के प्रति, क्या स्थिति, किसी निर्देश का, जहाँ तक उसका संबंध उनके कृत्यों और शक्तियों से है, अर्थ, अब तक कि संबंध द्वारा अस्पष्टता अशुद्धि न हो, संसद के प्रति निर्देश लगाया जाएगा, और विधिद्वारा राज्य के संविधान की धारा 91 में राज्यपाल के प्रति और राज्य के विधान मंडल द्वारा उक्त धारा में निर्देश का अर्थ क्रमशः राष्ट्रपति के प्रति और संसद या उसके सदस्यों के प्रति निर्देश लगाया जाएगा ;

परन्तु इनमें की कोई बात राज्य संविधान की धारा 26 की उपधारा (1), धाराएं 27 से 31 तक (जिसमें वे दोनों सम्मिलित हैं), धारा 132, धारा 143 और दूसरे अनुसूची के पैरा 1 से 8 तक (जिसमें वे दोनों सम्मिलित हैं) के उत्तरा भाग तथा धारा 28 की धारा और न राष्ट्रपति को इस खंड के उपखंड (1) के अधीन, उस सीमा तक जहाँ कि वह उक्त राज्य के राज्यपाल के सहान से कार्य करने से निवारित करेगी ;

- (4) संविधान में, या राज्य संविधान में राज्य के विधान मंडल के या उनके द्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यही होना चाहिए मानो वह अधिनियमों या विधियों का ही उल्लिखित करता है जो इस उद्घोषणा के अन्तर्गत किए गए या राष्ट्रपति द्वारा या संविधान के अनुच्छेद 157 के खंड (1) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारों द्वारा राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं, और अन्तर्गत कर्तव्य का कारण खंड अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्या 20) और साधारण खंड अधिनियम 1997

(1897 का 10) का उत्तरा भाग जितना राज्य की शक्तियों पर लागू होता है, ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में इस प्रकार प्रमाण होना मानो यह उस राज्य के विधान मंडल का अधिनियम हो ।

नई दिल्ली,

दिनांक 18 जुलाई, 1990

आर. वेंकटरामन

राष्ट्रपति

[फा. सं. 5/11013/4/90-सौ. एन. आर.]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 1990

G.S.R. 647 (E):—The following Proclamation by the President is published for general information:

Whereas, I, R. Venkataraman, President of India, have received a report from the Governor of the State of Jammu and Kashmir and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India, as applicable to that State (hereinafter referred to as "the Constitution") and of the Constitution of Jammu and Kashmir (hereinafter referred to as "the State Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution, and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I:—

- assume to myself as President of India all the functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution and the State Constitution;
- declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and
- make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for

giving effect to the objects of this proclamation, namely:-

- (i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;
- (ii) the operation of the following provisions of the constitution and of the State constitution, is hereby suspended, namely:-

so much of the first proviso to article 3 of the Constitution as relates to the reference by the president to the Legislature of the state and the second proviso to that article; so much of clause (2) of article 151 of the Constitution as relates to the laying before the Legislature of the State of the report submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;

sections 35 to 41(both inclusive), so much of section 43 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State, section 44, sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 53, sections 54, 55, 56 and 57, clauses (b) and (c) of section 58 and the first proviso thereto, section 59, section 60, sub-section (2) of section 61 so far as it relates to clause (c) of, and the first proviso to section 58 and to section 60; sections 65, 66, 67, 71 and 72; sections 74, 75 and 76, sub-sections (3) and (4) of section 77, sections 85 to 88 (both inclusive) and so much of section 137 as relates to the laying of the report with a memorandum before

the Legislature of the State, of the State Constitution:

- (iii) any reference in the Constitution and the state Constitution to the Governor shall, in relation to the said State, be construed as a reference to the President, and any reference in the Constitution and the State Constitution to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and in particular, the reference in section 91 of the State Constitution to the Governor and to the Legislature of the State or the Houses thereof, shall be construed as references to the President and to Parliament or to the Houses thereof respectively;

Provided that nothing herein shall affect the provisions of sub-section (1) of section 26, sections 27 to 31 (both inclusive), section 122, section 143 and paragraph 1 to 8 (both inclusive) of the Second Schedule to the State Constitution or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;

- (iv) any reference in the Constitution or in the State Constitution to Acts or laws of, or made by, the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament, by virtue of this Proclamation or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution, and the Jammu and Kashmir General Clauses Act, 1977 (Act No. XX of 1977) and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) as

applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State.

New Delhi.
The 18th July, 1990

R. VENKATARAMAN,
PRESIDENT

ORDER

New Delhi, the 18th July, 1990

G.S.R. 648 (E):—The following Order by the President is published for general information:—

[F.No. V/11013/4/90—CSR]

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1990

आदेश

सा. का. नि. 648 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचना के प्रकाशन किया जा रहा है:—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन में जारी आज जुलाई, 1990 के अठारहवें दिन जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (1) के अनुसरण में, मैं एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार के सभी कृत्य तथा संविधान और जम्मू व कश्मीर के संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोग में सभी अधिकार, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के खंड (क) के पदों पर प्राप्त माना गया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निर्देशन द्वारा नियंत्रण के अधीन रहने हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा ही प्रयोज्य होंगी।

नई दिल्ली,
दिनांक 18 जुलाई, 1990

आर. वेंकटरामन,
राष्ट्रपति

[फा. सं. 5/11013/4/90—सी. एस. आर.]

नरेश चन्द्र,
गृह सचिव

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 18th day of July 1990, by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Jammu and Kashmir and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution and the Constitution of Jammu and Kashmir or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

New Delhi.
The 18th July, 1990.

R. VENKATARAMAN,
PRESIDENT

[F.No. V/11013/4/90—CSR]
(NARESH CHANDRA)

Home Secy.